

MPSE 008 (PART-3)

STATE POLITICS IN INDIA भारत में राज्य की राजनीति

Important questions with answers

महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर सहित

**FOR BOTH HINDI AND ENGLISH MEDIUM STUDENTS**

**TOPIC -1**

**DESCRIBE THE CHANGING PATTERNS OF POLITICS SINCE 1970'S.**

Emergence of Strong Leaders and Emergency

The 1970s were marked by the dominance of strong political leaders like Indira Gandhi. The period also witnessed the imposition of the Emergency from 1975 to 1977, which led to the suspension of civil liberties and a crackdown on political opposition.

1970 के दशक को इंदिरा गांधी जैसे मजबूत राजनीतिक नेताओं के प्रभुत्व द्वारा चिह्नित किया गया था। इस अवधि में 1975 से 1977 तक आपातकाल की घोषणा भी देखी गई, जिससे नागरिक स्वतंत्रता का निलंबन और राजनीतिक विपक्ष पर दमन हुआ।

1980s: Rise of Regional Parties and Identity Politics

The 1980s saw the rise of regional parties and the beginning of identity politics. The assassination of Indira Gandhi in 1984 led to a significant political shift, with her son Rajiv Gandhi becoming Prime Minister.

1980 के दशक में क्षेत्रीय पार्टियों का उदय और पहचान की राजनीति की शुरुआत हुई। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या ने एक महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन को जन्म दिया, जिसमें उनके पुत्र राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने।

#### 1990s: Coalition Politics and Economic Reforms

The 1990s witnessed the decline of single-party dominance and the rise of coalition governments. This period also marked the beginning of significant economic reforms under Prime Minister P.V. Narasimha Rao and Finance Minister Manmohan Singh.

1990 के दशक में एकल पार्टी के प्रभुत्व में गिरावट और गठबंधन सरकारों का उदय देखा गया। इस अवधि में प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह के तहत महत्वपूर्ण आर्थिक सुधारों की शुरुआत भी हुई।

#### 2000s: Political Stability and Economic Growth

The 2000s were characterized by relative political stability and substantial economic growth. The BJP-led NDA government under Atal Bihari Vajpayee introduced several key infrastructural projects. Later, the Congress-led UPA government, under Manmohan Singh, continued economic liberalization and social welfare programs.

2000 के दशक को अपेक्षाकृत राजनीतिक स्थिरता और महत्वपूर्ण आर्थिक विकास द्वारा चिह्नित किया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी के तहत भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने कई महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की शुरुआत की। बाद में, मनमोहन सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने आर्थिक उदारीकरण और सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों को जारी रखा।

#### 2010s: Rise of Nationalism and Majoritarian Politics

The 2010s saw the rise of nationalism and majoritarian politics, with the BJP, under Narendra Modi, winning a decisive victory in the 2014

and 2019 general elections. This period also witnessed significant policy changes such as demonetization and the implementation of the Goods and Services Tax (GST).

2010 के दशक में राष्ट्रवाद और बहुसंख्यकवाद की राजनीति का उदय देखा गया, जिसमें नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने 2014 और 2019 के आम चुनावों में निर्णायक जीत हासिल की। इस अवधि में नोटबंदी और वस्तु एवं सेवा कर (GST) के कार्यान्वयन जैसे महत्वपूर्ण नीति परिवर्तन भी देखे गए।

### 2020s: COVID-19 Pandemic and Its Political Impact

The early 2020s have been dominated by the COVID-19 pandemic, which has had profound social, economic, and political impacts. The government's handling of the crisis, vaccine distribution, and economic recovery plans have been central political issues.

2020 के दशक की शुरुआत में COVID-19 महामारी का प्रभुत्व रहा है, जिसने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव डाले हैं। संकट से निपटने, वैक्सीन वितरण और आर्थिक पुनर्प्राप्ति योजनाओं में सरकार की भूमिका केंद्रीय राजनीतिक मुद्दे रहे हैं।

## TOPIC 2

### EXPLAIN AREAS OF TENSIONS IN UNION AND STATE RELATIONS IN INDIA.

#### Fiscal Federalism

Tensions arise due to disagreements over the distribution of financial resources between the Union and the states. States often argue that they do not receive an equitable share of revenue from the central pool, impacting their ability to fund local development projects.

वित्तीय संघवाद के कारण संघ और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों के वितरण पर मतभेद होते हैं। राज्य अक्सर तर्क देते हैं कि उन्हें केंद्रीय पूल से राजस्व का न्यायसंगत हिस्सा नहीं मिलता है, जिससे स्थानीय विकास परियोजनाओं के लिए धन जुटाने की उनकी क्षमता प्रभावित होती है।

### Legislative Competence

Conflicts can occur regarding legislative powers. The Constitution of India divides subjects into the Union List, State List, and Concurrent List. Sometimes, there are disputes over which government (Union or state) has the authority to legislate on certain issues.

विधायी क्षमता को लेकर विवाद हो सकते हैं। भारत का संविधान विषयों को संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में विभाजित करता है। कभी-कभी, कुछ मुद्दों पर कानून बनाने के अधिकार को लेकर संघ और राज्य सरकारों के बीच विवाद होता है।

### Implementation of Central Laws

States may resist implementing central laws that they perceive as infringing upon their autonomy. This has been a point of contention, particularly with laws related to agriculture, environment, and labor reforms.

केंद्रीय कानूनों के कार्यान्वयन में राज्यों का विरोध हो सकता है, जिसे वे अपनी स्वायत्तता पर अतिक्रमण के रूप में देखते हैं। यह विशेष रूप से कृषि, पर्यावरण और श्रम सुधारों से संबंधित कानूनों के साथ विवाद का मुद्दा रहा है।

### Governor's Role

The appointment and actions of Governors can create friction. Governors are appointed by the President of India, and their role in state politics, especially in administering President's Rule, can lead to accusations of bias and misuse of power.

राज्यपालों की नियुक्ति और कार्यों से तनाव उत्पन्न हो सकता है। राज्यपालों को भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, और राज्य की राजनीति में उनकी भूमिका, विशेष रूप से राष्ट्रपति शासन के संचालन में, पक्षपात और सत्ता के दुरुपयोग के आरोपों को जन्म दे सकती है।

### Law and Order

Law and order is a state subject, but the Union government can intervene in the name of national security or in extraordinary circumstances. Such interventions are often viewed by states as encroachments on their jurisdiction.

कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है, लेकिन संघ सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर या असाधारण परिस्थितियों में हस्तक्षेप कर सकती है। ऐसे हस्तक्षेपों को राज्यों द्वारा उनके अधिकार क्षेत्र पर अतिक्रमण के रूप में देखा जाता है।

### Political Differences

Political differences between the ruling party at the center and those in power in various states can exacerbate tensions. Different political agendas can lead to a lack of cooperation and allegations of discrimination in resource distribution and policy implementation.

केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी और विभिन्न राज्यों में सत्ता में मौजूद पार्टियों के बीच राजनीतिक मतभेद तनाव को बढ़ा सकते हैं। विभिन्न राजनीतिक एजेंडों के कारण सहयोग की कमी और संसाधन वितरण और नीति कार्यान्वयन में भेदभाव के आरोप लग सकते हैं।

## Emergency Powers

The Union government has the power to impose President's Rule in a state under certain conditions, leading to the suspension of the state government. This provision has been a source of contention, especially when used for political reasons.

संघ सरकार के पास कुछ शर्तों के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की शक्ति है, जिससे राज्य सरकार का निलंबन हो जाता है। यह प्रावधान, विशेष रूप से राजनीतिक कारणों से उपयोग किए जाने पर, विवाद का स्रोत रहा है

## TOPIC-3

### WRITE A SHORT NOTE ON LINGUISTIC MINORITIES IN INDIA.

#### Linguistic Minorities in India

Linguistic minorities in India refer to groups whose native language is different from the official language of the state or region in which they reside. India is a diverse country with 22 officially recognized languages under the Eighth Schedule of the Constitution, and numerous other languages and dialects spoken across its states and territories.

भारत में भाषाई अल्पसंख्यकों से तात्पर्य उन समूहों से है जिनकी मातृभाषा उस राज्य या क्षेत्र की आधिकारिक भाषा से भिन्न है जहाँ वे रहते हैं। भारत एक विविध देश है, जहां संविधान की आठवीं अनुसूची के तहत 22 आधिकारिक मान्यता प्राप्त भाषाएं और विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों में बोली जाने वाली कई अन्य भाषाएं और बोलियां हैं।

#### Constitutional Provisions

The Indian Constitution safeguards the interests of linguistic minorities through various provisions. Article 29 ensures the protection of their language, script, and culture, while Article 30 grants them the right to establish and administer educational institutions of their choice.

भारतीय संविधान विभिन्न प्रावधानों के माध्यम से भाषाई अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है। अनुच्छेद 29 उनकी भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा सुनिश्चित करता है, जबकि अनुच्छेद 30 उन्हें अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और प्रबंधित करने का अधिकार प्रदान करता है।

### Government Initiatives

The government has established mechanisms like the Commissioner for Linguistic Minorities to address their grievances and ensure their rights. Various states also have specific measures to promote and preserve the languages of linguistic minorities.

सरकार ने उनकी शिकायतों का निवारण करने और उनके अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए आयुक्त जैसी व्यवस्थाएं स्थापित की हैं। विभिन्न राज्यों में भी भाषाई अल्पसंख्यकों की भाषाओं को बढ़ावा देने और संरक्षित करने के लिए विशेष उपाय हैं।

### Challenges

Despite these provisions, linguistic minorities often face challenges such as inadequate representation in the political and educational spheres, and limited access to government services in their native languages. Efforts to address these issues are ongoing.

इन प्रावधानों के बावजूद, भाषाई अल्पसंख्यकों को राजनीतिक और शैक्षिक क्षेत्रों में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व और अपनी मातृभाषाओं में सरकारी सेवाओं तक

सीमित पहुंच जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इन मुद्दों को हल करने के प्रयास जारी हैं।

### Cultural Preservation

Linguistic minorities play a crucial role in enriching India's cultural diversity. Efforts to preserve and promote their languages and cultural practices are essential for maintaining the country's rich heritage.

भाषाई अल्पसंख्यक भारत की सांस्कृतिक विविधता को समृद्ध बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनकी भाषाओं और सांस्कृतिक प्रथाओं को संरक्षित और बढ़ावा देने के प्रयास देश की समृद्ध विरासत को बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं।

Scholarly Minors